



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2008/ज्येष्ठ 6, 1930

No. 187]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2008/JYAISTHA 6, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2008

जांच शुरुआत

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी के आयातों पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा संबंधी जांच शुरुआत।

फा. सं. 15/16/2008-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अधिज्ञान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा की थी। प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की अधिसूचना दिनांक 31-7-2003 की अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इन जांच परिणामों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 24-10-2003 की अधिसूचना सं. 159/2003 के द्वारा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार यदि लगाए गए शुल्क को पहले वापस नहीं लिया जाता है तो ऐसे शुल्क लगाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर

इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा की जानी अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस संबंध में वर्ष 2006 की रिट याचिका सं. 16893 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है इसलिए यह जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त करने से पाटन एवं क्षति को जारी रहने अथवा इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी, निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार एतद्वारा निर्णायक समीक्षा शुरू करते हैं।

3. विचाराधीन उत्पाद

निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में वर्णित उत्पाद के समान है अर्थात् विटामिन सी और अधिकांशतः विटामिन सी के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त जैसे एस्कार्बिक एसिड, एल-जाइलोस्कोर्बिक एसिड, 3-ओक्सो-एल-गुलोफ्यूरैनोलेक्टोन (एनरॉल रूप), एल-3-केटोथियोएक्सस्यूरोनिक एसिड लैक्टोन आदि है जैसा कि प्रविष्टि सं. "मर्क इंडेक्स का 867" के अंतर्गत वर्णन किया गया है।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में यह सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2936.27 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

4. प्रक्रिया

- (I) जांच से यह निर्धारण होगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्क को लागू रखना जरूरी है और यदि शुल्क को हटाया या इसमें परिवर्तन अथवा दोनों किए जाते हैं तो क्या क्षति के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी :—

- (i) समीक्षा में दिनांक 31-7-2003 की अधिसूचना 14/14/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे। इस समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।
- (ii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2004 से मार्च, 2005; अप्रैल, 2005 से मार्च, 2006; अप्रैल, 2006 से मार्च, 2007 की अवधियाँ और जांच अवधि शामिल होंगी।
- (iii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान सभी आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस समीक्षा में लागू होंगे।

(II) सूचना का प्रस्तुत करना

घरेलू उद्योग के लिए इस अधिसूचना के जारी होने के चालीस दिनों (40 दिन) के भीतर निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग के लिए आवेदन पत्र) में सूचना और पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा इनकी पुनरावृत्ति होने या दोनों की संभावना से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें शुल्क को जारी रखने की जरूरत को न्यायोचित ठहराया गया हो।

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जाएगा :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
फैक्स : 91-11-23063418

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के लिए इसका एक अगोपनीय रूपांतर अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

(III) समय सीमा

घरेलू उद्योग से सूचना प्राप्त होने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों जिनके पते उपलब्ध हैं, को एक पत्र के जरिए अपनी लिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी जो पत्र जारी करने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिनका पता उपलब्ध नहीं है, भी घरेलू उद्योग से आवेदन की तारीख के 40 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रयोजनार्थ आवेदन का अगोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

(IV) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING
AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2008

INITIATION

(Sunset Review)

Sub. : Initiation of Sunset Review of the definitive anti-dumping duty imposed on imports of Vitamin C originating in or exported from China PR.

F. No. 15/16/2008-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Vitamin C (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country). The final findings notification of the Authority was published vide notification dated 31-7-2003. On the basis of findings, definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject country was imposed by the Department of Revenue vide notification No. 159/2003 dated 24-10-2003.

2. Initiation of Sunset Review

Whereas in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, Hon'ble Delhi High Court in WP No. 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory, therefore, the Designated Authority hereby initiate sunset review in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Anti-dumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. Product under Consideration

Product under consideration in the sunset review is same as was described in the original investigation i.e. Vitamin C and most commonly used synonyms of Vitamin

C like ascorbic Acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-Oxo-L-gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone, etc., as described under entry number "867 of MERCK INDEX".

It is classified under Custom Sub-heading 2936.27 in the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

4. Procedure

(I) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both :—

- (i) The review will cover all aspects of Notification 14/14/2002-DGAD dated 31-7-2003. The country involved in this review investigation is China PR.
- (ii) The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April 2007 to 31st March 2008. The injury investigation period will however cover the periods April, 2004—March, 2005, April, 2005—March, 2006, April, 2006—March, 2007 and the POI.
- (iii) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

(II) Submission of Information :

The Domestic industry is required to submit information on prescribed *pro forma* (Application for Domestic industry) and information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both substantiating the need for continuation of duty within forty days (40 days) of issue of this notification.

The exporters in subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and

manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address :

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce
Udyog Bhavan, New Delhi-110011

Fax : 91-11-23063418

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

(III) Time Limit :

On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from date application from Domestic industry. For this purpose non-confidential version of the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

(IV) Inspection of Public File :

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority